I. ANNUAL REPORT (1967-68) OF THE CARDAMOM BOARD, ERNAKULAM

II. ANNUAL REPORT (1967-68) OF THE RUBBER BOARD

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : Sir, I beg to lay on the Table :—

(a) A copy of the Annual Report on the working of the Cardamom Board, Ernakulam, for the year 1967-68.

(b) A copy of the Annual Report on the activities of the Rubber Board for the year 1967-68.

[Placed in Library. *See* No. LT-2777/68 for (a) and (b)]

I. THE COTTON TEXTILES (CONTROL) FOURTH AMENDMENT ORDER, 1968

II. THE COTTON TEXTILES (CONTROL) FIFTH AMENDMENT ORDER, 1968

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : Sir, I also beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (in English) of the Ministry of Commerce, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 :—

(i) Notification S.O. No. 4138, dated the 11th November, 1968, publishing the Cotton Textiles (Control) Fourth Amendment Order, 1968.

(ii) Notification S.O. No. 4139, dated the 11th November, 1968, publishing the Cotton Textiles (Control) Fifth Amendment Order, 1968.

[Placed in Library. *See* No. LT-2776/68 for (i) and (ii).]

STATEMENT BY MINISTER *RE* BANARAS HINDU UNIVERSITY

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : Sir, during the course of discussion on the Banaras Hindu University on December 13, 1968, all sections of the House had pressed for appointment of a Committee of Inquiry by the Visitor. I had assured the Members that I would convey their feelings to the Visitor and advise him to set up such a Committee under the provisions of the Act.

The Visitor has since directed that an inquiry in respect of the recent state of unrest and agitation in the Banaras Hindu University shall be made by a Committee consisting of the following :—

(1) Dr. P. B. Gajendragadkar, Vice-Chancellor, Bombay University—Chairman.

(2) Mr. Justice V. S. Desai, Judge, Bombay High Court—Member.

(3) Prof. S. K. Bose, Chairman, Inter-University Board of India—Member.

(4) Prof. K. C. Mehrotra, Vice-Chancellor, University of Rajasthan—Member.

The terms of reference of the Committee are as under :

"To inquire into the recent state of unrest and agitation in the University and to make such recommendations as may be considered necessary or expedient for remedying the situation and for improving the general tone of discipline and law and order in the University."

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir, I have a submission to make. My submission in the first place is this : Has the honourable Minister's attention been drawn to the public statement to the Bress by the present Vice-Chancellor of the Banaras Hindu University in which he has squarely blamed the Government of India, and the Education Minister in particular, for the situation which has arisen in the Banaras Hindu University? This is a very serious matter. In view of this thing, Sir, would it not be proper that pending the question of his final disposal, he should be asked to keep aloof from the University because, otherwise, the investigation is not going to be fair and proper? I tell you Mr. Rajnarain will throw more light on the subject. All

that I say to you Sir, is, kindly consider that he is in charge of the University, he has the control of the University. We are sending an investigation commission .

SHRI M. P. SHUKLA (Uttar Pradesh) : Sir, . . .

SHRI BHUPESH GUPTA : Why do you take my time? Please for goodness's sake . .

All that I say is that his presence there will be repugnant to the purpose of the enquiry because he gave his verdict not only locally but he also held the honourable Minister and his Ministry responsible Now, Sir obviously witnesses will not be forthcoming, and there will always be a constant intimidation of those students and teachers who may like to come and give their truthful evidence Sir, then again, various documents may have to be seen, various correspondence may have to be seen. A discovery of the background would be of vital importance in the context of this enquiry. Are we, Sir, to leave it in the hands of the man who now stands in the dock indirectly at least? Kindly consider this, Sir He refused to hold an enquiry. He delayed it even when the Minister wanted them to appoint an enquiry commission which we did not like because we wanted the Government to appoint it. . .

(Interruptions)

SHRI M P SHUKLA : Sir, . . .

(Interruptions)

MR CHAIRMAN : You will have your say I shall give you an opportunity.

SHRI BHUPESH GUPTA. Therefore, Sir, in view of all these things, my submission is that it should be done like that. The Minister should convey at least his Government's desire in fairness to the enquiry commission that the Vice-Chancellor should well leave the place. For us we want his removal Now, Sir, we stand vindicated. You will agree, Sir, for this vindication we have been precisely agitating for an enquiry of this kind. It is we of the opposition who stand vindicated by the action of the Government itself Kindly listen to us in regard to the follow-up matter

DR TRIGUNA SEN Sir, his first point was whether my attention has been drawn to the newspaper reports of a Press conference held by Dr Joshi. Yes Sir I have seen the report I can only say, it is unfortunate His second point was that the V. C should be removed for the convenience of the enquiry I do not agree to that. Besides, it is also not a feasible proposition.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : क्या शिक्षा मत्री को इस बात की जानकारी है कि वाइस चासलर ने कौमिल की मीटिग मे स्वत कहा था कि यदि विजिटर की इन्क्वायरी कमेटी बनेगी तो मै इस्तीफा दे दूगा? क्या शिक्षा मत्री जी को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालय टीचर्स की एक मीटिग हुई जिसमें 12 वक्ता बोले और जिसमें 8 वक्ताओं ने वाइस चासलर के कन्डक्ट पर, उनके आचरण पर इतना उग्र प्रहार किया जिससे वाइस चासलर महोदय घबडाए और घबडा कर उन्होंने खुद यह बयान दिया कि विद्यार्थियों के विरुद्ध विद्यार्थियो को इस्तेमाल करने का मेरा तरीका नाकामयाब सिद्ध हो गया । इसको मै कबूल करता हू? जो जो टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे उन्होंने स्वत इस्तीफा दे दिया अपनी गलती मान कर—तमाम अध्यापक इतने रज मे है कि टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने वाइस चासलर के कुकर्मो पर पर्दा डालने की कोशिश की—इसलिए उसने भी इस्तीफा दे दिया । क्या शिक्षा मत्री को पत्रों की कौमिल की बैठक की यह खबर भी मालूम है कि जो विजिटर की कमेटी बनी है उसमे एक पर्यवेक्षक जाता है. पर्यवेक्षक सामान्यत वाइस चासलर जाय या किसी को भेजे तो उसने कहा कि वाइस चासलर जायं आब्जर्वर बन कर या किसी अपने नामिनी को भेजे, तो जब वाइस चासलर के विरुद्ध जांच हो रही है, सारी चीज की बुनियाद मे वाइस चांसलर महोदय खुद है तो पर्वेक्षक, आब्जर्वर के रूप में उस कमेटी में उनका सर्वदा विद्यमान

[श्री राजनारायण]

रहना क्या उचित होगा ? क्या इसके रहते गवर्नमेंट कोई ऐसी कार्यवाही कर सकती है ? जिसके ऊपर चार्ज है वही आब्जर्वर बन कर उस कमिशन के सामने रहेंगे तो खुल कर अध्यापक सारी बातों को नही कह पायेंगे । तो मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि वाइस-चांसलर आब्जर्वर के रूप में न रहें और कोई चाहे दूसरा उनका नामिनी रहे तो अलग बात है ।

और तीसरी बात यह है कि इस सदन में जो सरकार की घोषणा हुई थी उसमें एक व्यक्ति का कमिशन बनाने की बात थी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ही जगह चार का कैसे बन गया ।

श्री ए०पी० जैन:(उत्तर प्रदेश)यह तो अच्छा है ।

श्री राजनारायण : ठीक है अच्छा हो । मैं प्रेसिडेंट साहब से भी मिला इस बात को ले कर एक हवा थी, एक रुमर थी कि एक की कमेटी न बने, ज़्यादा की बने, चार की बने या पाच की बने । तो हम यह जानना चाहते है कि सरकार की घोषणा थी कि एक की ही होगी तो फिर यह चार की कैसे बनी ।

और ज़रा इसका कांस्ट्रक्शन देखा जाय । एक नावेल चीज़, एक नई चीज़ आप पायेंगे । एक एक्टिंग जज है और वह जो एक्टिंग जज है वह एक रिटायर्ड जज के मातहत उसके चैरमनशिप में, सदस्य बन रहा है ।

श्री महावीर प्रसाद भार्गव :(उत्तर प्रदेश) वह सुप्रीम कोर्ट के हैं और यह हाईकोर्ट के हैं ।

श्री राजनारायण : यह मैं जानता हूं मगर यह एक नई चीज़ है ।

श्री महावीर प्रसाद भार्गव : नया क्या है ?

श्री राजनारायण : नई चीज़ है । इसको भी देखना चाहिये । मैं सरकार की बात जान लूं, जो मुझे जानकारी है वह तो है । तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति क्यों आई कि एक की जगह चार व्यक्तियों का कमिशन बना ? कहीं बाहर से दबाव आया, ऐसा दबाव आया कि सरकार झुकी ।

पांचवी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कमिशन बनने की बात सदन में हो चुकी तो कमीशन के बनने की बात होने के बाद जो विद्यार्थी वहां से निष्कासित हुये उनका निष्कासन रद्द होना चाहिये और अगर यह कमिशन उन विद्यार्थियो को दोषी ठहराये तब तो उनके ऊपर जो कार्यवाही होनी हो वह कार्यवाही होनी चाहिये । मेरा यह निवेदन है ।

और, श्रीमन, आपको मालूम है कि 18 दिसम्बर को हमने अखबार की कटिंग और अखबार दोनों आप को पढ़ कर सुनाया और आपको एक चिठठी लिखी जिसको आपने कहा कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर के पास भेज दूगा, उसमें हमने यह साफ लिखा था कि उपकुलपति ने स्वयं अध्यापको की सभा में इस बात को स्वीकार किया है कि विद्यार्थियों के आन्दोलन को दबाने के लिये विद्यार्थियों के इस्तेमाल का उनका प्रयोग विफल हो गया । उसमे हमने लिखा कि अखबारों की कतरन संलग्न है । तो इन सब बातों को जानते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय को सामान्य अवस्था में लाने के लिये, पूज्य महामना मालवीय जी की धवल-कीर्ति को कलंकित न होने देने के लिये, यह जो इंक्वायरी हो रही है यह फार्स न हो, यह नौटंकी न मानी जाय, इसकी पवित्रता और शुद्धता को कायम रखने के लिये जब तक जांच होती है तब तक वाइस-चांसलर महोदय को वहां पर नहीं रहना चाहिये वर्ना वह जांच को प्रभावित करने के लिये जैसे अब तक तमाम कुकर्म किये है वैसे ही तब भी करेंगे ।

DR. TRIGUNA SEN : Sir, the hon. Member has asked several questions, whether मेरी जानकारी है कि नहीं है । No. 1, whether the Vice-Chancellor threatened resignation if a Committee is appointed, whether the Vice-Chancellor confessed that his policy was wrong. . .

SHRI RAJNARAIN : Failed.

DR. TRIGUNA SEN : . . . whether the teachers resigned from the Teachers' Association as a protest, and

lastly whether the Executive Committee would nominate the Vice-Chancellor to be the Observer in the Committee Sir, मे री जा न का री न ही है । He knows more things of Banaras than I do My knowledge is only from the reports in the papers I would only request the hon Member : 'Do not give your ears to rumours'.

श्री राजनारायण· मै इतना ही निवेदन करूगा कि कौसिल की प्रोसीडिग्स मत्री जी मगा ले और खुदा के लिये इस सरकार को चलाने के लिये मत्री लोग यह न सोचे कि इनको असत्य बोलना ही जरूरी है ।

श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल : सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मत्री जी ने भूपेश गुप्त और श्री राजनारायण जी की इस माग को कि वाइस-चासलर को पहले ही से सजा दे दी जाय जो उसको ठुकरा दिया उसके लिये मै उनको धन्यवाद देना चाहता हू । मै यही निवेदन करना चाहता हू कि जब कमेटी नियुक्त हो गई है तो निष्पक्ष रूप से वह कमेटी जाच करे और जो अपराधी होगे उनको सजा तब दी जायगी जब कि उनका अपराध सिद्ध होगा । इस माननीय सदन के कमीशन की माग की थी और वह एक व्यक्ति का हो या कई व्यक्तियो का हो ऐसा कुछ नही कहा गया था और इसलिये यदि कमिशन कई व्यक्तियो का नियुक्त किया गया है तो ज्यादा अच्छा ही होगा, यदि एक ही व्यक्ति का होता तो वह उतना ज्यादा अच्छा नही होता और तब शायद माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के इस बात को माग करते कि यह क्या है सरकार ने कोई अपने पिट्ठ् को बैठा दिया है और वह जो चाहेगी वह करेगी । इसलिये मै निवेदन करना चाहता हू कि बनारस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो बाते माननीय सदस्यो द्वारा कही जा चुकी है और अब भी कही जा रही है, विरोधी पक्ष की ओर से हो रही है, उसकी सफाई तब हुई होती जब कि वहा एक रेफरेडम विद्यार्थियो और अध्यापको से लिया जाय, वाइस-चासलर को अलग कर के, और तब पता चलता, लेकिन अब यह जो जाच होगी उससे पूरी बाते सामने आ जायेगी । यही मेरा निवेदन है ।

श्री सुन्दर सिह भंडारी(राजस्थान) : मै मत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हू कि विजिटर के द्वारा जिस कमेटी की नियुक्ति की गई है इसकी क्या आवश्यकता इस कारण पडी कि वाइस-चासलर किसी भी प्रकार की जाच कराने के लिये तैयार नही थे या यह स्थिति इसमे से निर्माण हुई कि यहा पर हुये विवाद के अनुसार केन्द्रीय सरकार की सलाह से एक कमेटी नियुक्त होने वाली थी पिछले दिनो में जब यहा चर्चा चली तो शिक्षा मत्री ने यह कहा कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी और सरकार के बीच मे नेगोशियन्स इस विषय में चल रहा है । ऐसा मै समझता हू कि उस दिन जो सदन में यह माग की गई कि यह नेगोशियन्स कुछ भी चल रहा हो लेकिन केन्द्रीय सरकार को विजिटर द्वारा कमेटी नियुक्त कर देनी चाहिये और इसी के अन्तर्गत यह कमेटी नियुक्त हुई है । या वाइस चासलर किसी भी प्रकार की जाच के लिये तैयार नही थे, कोई भी जाच कमेटी नियुक्त नही करवाना चाहते थे इसलिये यह कमेटी नियुक्त हुई ? इस एक चीज के बारे मे स्पष्टीकरण हो जाने के बाद फिर मै समझता हू कि स्थिति को समझने मे मदद मिलेगी ।

दूसरे यह कि यह कमेटी जो बिठाई गई है जाच करने की वह वाइस-चासलर के काडक्ट पर जाच करने के लिये बिठाई गई है या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय मे पिछले दिनो मे जो घटनाये हुई और जिसके कारण अशान्ति का वातावरण निर्माण हुआ उस अशान्ति की घटनाओ पर जाच करने के लिए यह कमेटी बनाई गई है ?

श्री राजनारायण. घटनाओ की जाच के लिये ।

DR TRIGUNA SEN . The hon. Member has asked two questions : (1) what are the terms of reference of the Committee which I mentioned, and (2) whether this Committee is going to find out the activities or sit on judgment on the activities of the Vice-Chancellor. If I am allowed, I will re-read the terms of reference of the Committee which are as under :

> "To inquire into the recent state of unrest and agitation in the University . ."

SHRI BHUPESH GUPTA : On a point of order. This is for Mr. Gajendragadkar and the Committee to interpret it. It is highly wrong. He has read out the terms of reference. The matter is closed. If the Government wants to modify, let them take your leave and come again. He cannot prejudice it and give an interpretation .

श्री राजनारायण : श्रीमन्, वह उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते ।

MR. CHAIRMAN : He is merely reading out.

SHRI BHUPESH GUPTA : He is interpreting it.

DR. TRIGUNA SEN: He will not allow anybody to listen. My friend asked whether the Committee will be asked to enquire into the activities of the Vice-Chancellor. I am just reading out the terms of reference which I had already done.

SHRI BHUPESH GUPTA: You said 'no'.

DR. TRIGUNA SEN : Will you use your earphone?

MR. CHAIRMAN : He wanted to reply by reading what is contained there.

श्री पीताम्बर दास : वह पढ़ तो सकते हैं । क्या वह पढ़ भी नहीं सकते ।

DR. TRIGUNA SEN : I may refer to Mr. Bhandari's question "To inquire into the recent state of unrest and agitation in the University and to make such recommendations as may be considered necessary or expedient for remedying the situation and for improving the general tone of discipline and law and order in the University."

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Let the Minister go on.

DR. TRIGUNA SEN : As regards the first question of Mr. Bhandari, Sir, will you allow me to repeat the events?

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : You may repeat them.

DR. TRIGUNA SEN : Following the disturbances in the University in October/November, 1968, the Government came to the conclusion that it was necessary to set up a commitee to inquire into the matter and to suggest remedial measures. Such a committee could have been appointed by the Visitor under the provisions of the Act. But I felt that if the Executive Council of the University itself undertook to cause an inquiry to be made, the purpose would be equally served, provided the personnel of the committee was such that it evoked confidence in the public mind. The Vice-Chancellor was, however, opposed to any inquiry even though the P.A.C. was stationed in the campus and disturbances were taking place. He however subsequently agreed to propose to the Executive Council of the University, which was due to meet on November 15/16, 1968, that the Council pass a resolution for the appointment of a committee. He also agreed that the personnel of the Committee would be settled in consultation with Government. The Vice-Chancellor wrote to me on November 12 confirming that he would move the Executive Council to appoint a committee. In doing so he also mentioned certain names which had been previously discussed. But he was immediately informed that the personnel of the committee might undergo some change. The Vice-Chancellor was further advised to place all the facts before the Executive Council regarding the discussions that he had had with Government and obtain an authorisation from the Executive Council to settle the personnel of the committee by further discussion with us. In fact he later told me himself that he did not inform the Executive Council about the assurance given to me for settling the personnel of the committee in consultation with the Government. This resulted in the Executive Council passing a resolution for the appointment of a committee but at the same time drawing up a panel of names of Judges and educationists from out of which the committee might be constituted. Had the Vice-Chancellor taken the Executive Council into confidence, I have every reason to believe—as I mentioned to

him also—that the Executive Council would have given him the necessary authorisation which would have left the door completely open for the settlement of the question, and the committee would have been appointed much earlier.

While the resolution of the Executive Council to authorise the Vice-Chancellor to constitute a committee from out of the panel of names decided upon by the Council was communicated to the Ministry over the telephone on the 18th November, this did not give any information about the names of the persons included in the panel. It was only on the 25th November that the Vice-Chancellor came here, met me and informed me about these names. But he also added that the Executive Council had asked him to contact the persons included in the panel in the order indicated in the list. Further, if any change was desired, the matter would have to go back to the Executive Council. Members will appreciate that this hardly left any room for any meaningful discussion on the constitution of the committee.

Despite the non-fulfilment of the assurance given to me by the Vice-Chancellor originally, I was anxious that some way should be found for constituting a committee of inquiry under the aegis of the Executive Council of the University itself. But meanwhile the situation in the University deteriorated and I also saw no evidence of any initiative on the part of the Vice-Chancellor to speed up action that would enable the University and the Government to settle the question. On December 8, the police entered the hostels and are reported to have beaten the students mercilessly. The Vice-Chancellor himself admitted that this had worsened the situation. There was a strong feeling generally, which was also expressed in this House on December 13, that a committee of inquiry should be set up without any further delay by the Visitor. I took immediate action on this with a view to constituting the committee. I can tell the House, Sir, through you that even while I was coming to this House on the 13th of December, I had a discussion with the Vice-Chancellor. I requested him to request the Visitor to appoint a committee which, if done, would have been dignified for the autonomy of the University and for the Vice-Chancellor. But, Sir, he did not do so, and I came to this House.

It is most unfortunate that my desire to let the University set up its own committee in consultation with the Government should have been construed by the Vice-Chancellor as indecision on the part of the Government and that the delay in the appointment of a committee should be attributed to it. Had the Vice-Chancellor acted in accordance with the assurance given by him to me prior to the November meeting of the Executive Council, the committee would have been set up much earlier and would, in fact, have been functioning by now.

This is the whole story. I have not kept anything secret.

श्री राजनारायण : श्रीमन, इस लेटर से पता चल जायगा कि वाइस चान्सलर कितने कुकर्मी है।

(Interruptions)

श्रीमन्, मुझे एक और निवेदन करना है कि शिक्षा मंत्री जी यहां उपस्थित है और इसी सदन में उन्होंने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के अध्यापकों के बारे में राज्यपाल 20 तारीख को आयेंगे, एक दिन के बाद फैसला हो जायगा मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अध्यापकों के बारे में क्या हुआ?

MR. CHAIRMAN : Message from the Lok Sabha. Secretary.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारे सवाल का क्या हुआ ? मैंने अभी निवेदन किया कि इस सदन में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि राज्यपाल बुलाये गये हैं। राज्यपाल यहां आए, तीन दिन यहां रहे, प्रेज़ीडेन्ट भवन में रहे ...

MR. CHAIRMAN : Message from the Lok Sabha.